

## बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण 2016-17

### अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में एक देदीप्यमान प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरी है तथा यह विश्व की एक सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही एक बड़ी अर्थव्यवस्था का रूप ग्रहण कर चुकी है। केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2015-16 में स्थिर बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. में 7.6 प्रतिशत की विकास दर पिछले तीन वर्षों की विकास दर अर्थात् 2014-15 में 7.2 प्रतिशत, 2013-14 में 6.6 प्रतिशत तथा 2012-13 में 5.6 प्रतिशत के अनुरूप है। यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यह विकास दर वैश्विक स्तर पर मांग में कमी आने, जिससे भारत के निर्यात में काफी कमी आई तथा लगातार दो वर्षों तक मानसून सामान्य से कम रहने के कारण कृषि उत्पादों तथा उत्पादकता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बावजूद प्राप्त किए जाने का अनुमान है।

राजकोषीय विवेकशीलता, मुद्रास्फीति की निम्न दर, चालू खाता घाटा कम स्तर पर बने रहने तथा विदेशी मुद्रा आरक्षित भंडार के उच्च स्तर पर बने रहने से बृहत-आर्थिक स्थायित्व में पर्याप्त सुधार आया है। वर्ष 2015-16 में सरकार ने एक उत्कृष्ट संतुलनकारी कार्य किया अर्थात् सरकार ने राजकोषीय विवेकशीलता को बनाए रखकर तथा पूंजी व्यय में वृद्धि करते हुए चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप उच्च मात्रा में केंद्रीय राजस्व का अंतरण किया। वर्तमान वर्ष के दौरान भी सरकार की विवेकशील खाद्य आपूर्ति प्रबंधन नीति के साथ ही भारत में कच्चे तेल और जिन्सों के मूल्यों में पर्याप्त कमी से सामान्य मूल्य स्तर में कमी आई। चालू खाता घाटे में कमी आने तथा पूंजी अंतर्वाह में मामूली वृद्धि होने से विदेशी मुद्रा भंडार में 2015-16 की पहली छमाही में 10.6 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई। 5 फरवरी, 2016 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 351.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर था। इन सबसे यह ज्ञात होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक चुनौतियों का प्रभावी रूप से सामना किया है तथा भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र गति से विकास के पथ पर अग्रसर रहने की भारी संभावना है।

इस वर्ष भी विकास तथा बृहत-आर्थिक स्थायित्व पर नजर रखते हुए 2014-15 में सृजित सुधार की गति जारी रही। पिछले वर्ष ढांचागत बाधाओं को समाप्त करके, "मेक इन इंडिया" पहल तथा व्यवस्था आरंभ करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आनुषंगिक उपायों को करके, वास्तविक उपभोक्ता को लाभ की राशि सीधे उसके खाते में अंतरित करके तथा अन्य उपायों द्वारा

कार्यक्रम सुपुर्दगी में सुधार लाकर, बैंकिंग सेवाओं को गहन बनाकर बचत तथा वित्तीय संपर्कों के संबंध में प्रोत्साहन तथा विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाकर अर्थव्यवस्था के मार्ग की बाधाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया इस वर्ष भी जारी रखी गई। कुछ नई पहलें जैसेकि बीमार विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में आमूल बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संपुष्टीकरण की योजना उदय (उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना), उभरती हुई उद्यम क्षमता का उपयोग करने के लिए "स्टार्ट अप इंडिया" जैसी नई पहलों से चालू सुधार उपायों को बल मिला है। इन सुधारों को लागू करने से व्यावसायिक माहौल में सुधार आया है तथा निवेशकों के विश्वास में वृद्धि हुई है जिसे बहु पक्षीय संस्थाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है तथा जो अर्थव्यवस्था की तीव्र विकास दर एवं देश में निवेश के अंतर्वाह में वृद्धि से प्रदर्शित होता है।

### स.घ.उ. विकास दर

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2015-16 में 7.6 प्रतिशत होने का अनुमान है जो 2014-15 में प्राप्त 7.2 प्रतिशत विकास दर की तुलना में उच्च स्तर पर है। कृषि, उद्योग और सेवाओं में विकास दर 2015-16 में क्रमशः 11 प्रतिशत, 7.3 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 2014-15 में यह आंकड़ा क्रमशः (-)0.2 प्रतिशत, 5.9 प्रतिशत और 10.3 प्रतिशत था। यह विनिर्माण द्वारा प्रेरित औद्योगिक वृद्धि में तेजी को दर्शाता है जिसके वर्ष 2014-15 में दर्ज 5.5 प्रतिशत की तुलना में 2015-16 में 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है। कृषि में वृद्धि लगातार दूसरे वर्ष भी मानसून में कमी के कारण कम स्तर पर बनी रही। अप्रैल-दिसंबर 2015 (प्रथम 3 तिमाहियों में) के दौरान जीडीपी वृद्धि 7.5 प्रतिशत थी जबकि 2014-15 की विकास दर में वृद्धि इसी समयावधि में 7.4 प्रतिशत थी।

मांग के संदर्भ में, निजी अंतिम उपभोग व्यय में वर्ष 2015-16 में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो विकास दर में वृद्धि का प्रमुख प्रेरक रही है। नियत निवेश की वृद्धि वर्ष 2014-15 के 4.9 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 5.3 प्रतिशत हो गई। निर्यात और आयात में 2015-16 के दौरान 6.3 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है। निर्यात में कमी मुख्य रूप से विश्वभर से मांग में कमी आने तथा आयात में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम के मूल्यों में गिरावट के कारण हुई है।

## कृषि

वर्ष 2015 में दक्षिण-पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान देश में औसत दीर्घावधिक वर्षा की तुलना में 14 प्रतिशत कम वर्षा हुई। चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2014-15 में खाद्यान्नों का उत्पादन 252.7 मिलियन टन था (चावल 104.8 मिलियन टन तथा गेहूँ 88.9 मिलियन टन) जबकि 2013-14 (अंतिम अनुमान) के दौरान 265.0 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ था। 2014-15 में दालों का उत्पादन 17.2 मिलियन टन, गन्ने का 359.3 मिलियन टन, तिलहन का 26.7 मिलियन टन और कपास का उत्पादन प्रत्येक 170 कि. ग्राम की 35.5 मिलियन गांठ होने का अनुमान लगाया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा 16.9.2015 को जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2015-16 के दौरान कुल खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन 124.1 मिलियन टन होने का अनुमान है जबकि 2014-15 में 120.3 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था।

वर्ष 2014-15 में कृषि ऋण का प्रवाह बढ़कर 8,45.328 करोड़ रुपये (अंतिम) हो गया जबकि 2013-14 में यह राशि 7,30,123 करोड़ रुपये थी। 2015-16 के लिए कृषि ऋण प्रवाह का लक्ष्य 8,50,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था, जिसमें से 30 सितंबर, 2015 तक 5,03,898 करोड़ रुपये (अंतिम) का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया।

## कीमतें

वर्ष 2015-16 में सामान्य कीमतों में लगातार कमी का रुझान बना रहा। भारत में कच्चे तेल की कीमतों में प्रत्यक्ष तथा दूसरे चक्र के प्रभावों के कारण उल्लेखनीय गिरावट होने के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी सामान्य मुद्रास्फीति में अंशतः गिरावट रही। सीपीआई (संयुक्त) श्रृंखला पर आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान कम होकर 4.9 प्रतिशत रह गई जबकि वर्ष 2014-15 के दौरान यह 5.9 प्रतिशत थी। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) के संदर्भ में मापित खाद्य मुद्रास्फीति घटकर 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान 4.8 प्रतिशत रह गई जबकि 2014-15 के दौरान यह 6.4 प्रतिशत थी। सीपीआई आधारित कोर मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) भी एक सीमा के भीतर बनी रही तथा मार्च 2015 के 4.2 प्रतिशत से मामूली बढ़कर जनवरी 2016 में 4.7 प्रतिशत हो गई। कोर मुद्रास्फीति में गिरावट मुख्य रूप से आवास(किराया), परिवहन, संचार, शिक्षा तथा अन्य सेवाओं की कीमतों में कमी आने के कारण हुई।

वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के वैश्विक रुझान के पश्चात् हेडलाइन थोक मूल्य सूचकांक में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से गिरावट आई। नवम्बर, 2014 से थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति नकारात्मक स्तर पर रही है और 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में इसका औसत (-)2.8 प्रतिशत रहा, जबकि 2014-15 में यह 2.0

प्रतिशत रहा था। ईंधन और विद्युत समूह में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में 2014-15 में (-)0.9 प्रतिशत से 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में (-)12.3 प्रतिशत की अत्यधिक गिरावट आई। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मूल मुद्रास्फीति 2014-15 में 2.4 प्रतिशत से 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में गिरकर (-)1.5 प्रतिशत रह गई। इस वर्ष मानसून सामान्य से कम रहने और वर्ष की दूसरी छमाही में दालों तथा कुछेक अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में यदाकदा वृद्धि होने के बावजूद, थोक मूल्य सूचकांक संयुक्त खाद्य मुद्रास्फीति संयत रही।

खाद्यान्नों के बफर स्टॉक के जरिए सरकार की कुशल खाद्य आपूर्ति प्रबंधन नीति और कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी से 2015-16 के दौरान आवश्यक वस्तुओं की कीमतें संयत रही। मुद्रास्फीति में कमी आने से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2015 के दौरान नीतिगत रेपो दरों में 125 आधार अंकों तक की कमी करने का पथ प्रशस्त हुआ।

## उद्योग और सेवाएं

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र 2015-16 की प्रथम तीन तिमाहियों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। अप्रैल-दिसंबर, 2015 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3.1 प्रतिशत अर्थात् गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 2.6 प्रतिशत से अधिक रहा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के क्षेत्रवार वर्गीकरण के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर, 2015-16 के दौरान विद्युत क्षेत्र में 4.5 प्रतिशत, विनिर्माण क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत और खनन क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्रों में वृद्धि की गति में और वृद्धि में बाधक कारणों में ये सम्मिलित हैं: अवसंरचनात्मक बाधाएं और कम विदेशी मांग। उपयोग-आधारित श्रेणियों में, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में अप्रैल-दिसंबर 2015-16 के दौरान वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

2015-16 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार, सेवा क्षेत्र, जो चालू मूल्य कीमतों पर भारत के योजित सकल मूल्य का 53.3 प्रतिशत बैठता है, में 9.2 प्रतिशत की वृद्धि (स्थिर मूल्यों पर) होने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र संबंधी कार्यकलापों में, क्षेत्र यथा: व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और सेवाएं; तथा वित्तीय, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में 2015-16 में ठोस वृद्धि दर दर्ज होने का अनुमान है।

## मौद्रिक घटनाक्रम

भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार-बिंदुओं की कटौती करके इसे 7.75 करने और तत्पश्चात् 4 मार्च, 2015 और 2 जून, 2015 को 100 आधार बिन्दुओं- 25 आधार बिन्दु प्रत्येक की संचयी कटौती तथा 29 सितम्बर, 2015 को और 50 आधार बिन्दुओं की कटौती के साथ 15 जनवरी, 2015 को अपने मौद्रिक नीतिगत दृष्टांत में परिवर्तन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 फरवरी, 2016 को छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा में नीतिगत रेपो रेट 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखी।

मुख्यतः सरकारी खर्च को नियंत्रित रखने के चलते 2015-16 की प्रथम तिमाही में नकदी की स्थितियां सामान्यतः तंग रहीं। तथापि, वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी तिमाही में, नकदी की स्थितियों में महत्वपूर्ण रूप से सुगमता रही क्योंकि सरकारी व्यय बढ़ गया और जमाराशियों की वजह से ऋण में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2015-16 की तीसरी तिमाही में, मुख्यतः त्यौहारी मौसम की चालू मांग के कारण नकदी की स्थितियां तंग रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार प्रचालनों के साथ दुहरी नकदी समायोजन सुविधा के तहत नियमित नकदी प्रचालनों के अतिरिक्त, टकराव संबंधी कारकों से उत्पन्न होने वाली नकदी की रोजमर्रा जरूरतों के निराकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न दर के रेपो तथा रिवर्स रेपो (ओवरनाइट तथा आवधिक) नीलामियों का आयोजन किया। तदनुसार, मौद्रिक नीति की भारित औसत मांग दर या प्रचालन लक्ष्य नीतिगत रेपो दर के आस-पास रहे।

### बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय समावेशन

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का कार्यनिष्पादन मंदा रहा। बैंकों के तुलन पत्रों में यह मंदी 2011-12 से लेकर 2015-16 के दौरान भी जारी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों की वृद्धि में मंदी का मुख्य कारण ऋणों और अग्रिमों (10 प्रतिशत से कम) में धीमी वृद्धि रहा। निवेश वृद्धि में भी मामूली कमी आई। ऋण वृद्धि में गिरावट औद्योगिक ऋण उठाने में कमी, कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा सूचित की गई आय की अत्यल्प वृद्धि और बढ़ती अनर्जक आस्तियों के कारण बैंकों द्वारा जोखिम लेने से बचने के रूप में सामने आई। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक स्रोतों की उपलब्धता के साथ, कार्पोरेट क्षेत्र की कंपनियों ने अपनी वित्तपोषण की जरूरतों को अन्य स्रोतों यथा-विदेशी वाणिज्यिक उधारों, कार्पोरेट बांडों तथा वाणिज्यिक पत्रों से पूरा करने की गति तेज कर दी।

प्रधान मंत्री जनधन योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान प्रारम्भिक बचत बैंक जमा खातों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। प्रारम्भिक बचत बैंक जमा खातों की संख्या सितम्बर, 2015 के अंत में 441 मिलियन तक पहुँच गई, जबकि मार्च, 2015 के अंत में यह 398 मिलियन थी। बैंकिंग शाखाओं की कुल संख्या मार्च, 2015 के अंत में 553,713 से सितम्बर, 2015 के अंत में बढ़कर 567,530 हो गई। 2015 में सभी भारतीयों, खासकर गरीबी और सुविधाविहीन लोगों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के सृजन हेतु बीमा और बैंकिंग क्षेत्रों ने तीन योजनाएं प्रारम्भ की। इन योजनाओं में शामिल हैं: प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना।

### विदेशी क्षेत्र

वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट और कमजोर मांग के कारण वैश्विक व्यापार के मूल्य में मंदी के प्रदर्शन से, भारत का

पण्य निर्यात मूल्य (सीमा शुल्क आधार पर) 2014-15 में 1.3 प्रतिशत गिरावट के साथ 310.3 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में, निर्यात वृद्धि में 17.6 प्रतिशत की गिरावट (गत वर्ष की इसी अवधि में 264.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 217.7 बिलियन अमरीकी डालर) आई। 2014-15 में 0.5 प्रतिशत गिरावट के साथ आयात 448.0 बिलियन अमरीकी डालर रहा। 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान आयात 324.5 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जोकि गत वर्ष की इसी अवधि में 383.9 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 15.5 प्रतिशत कम रहा। पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) का आयात 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में 41.4 प्रतिशत गिरावट के साथ 73.1 बिलियन अमरीकी डालर रह गया, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यह 124.8 बिलियन अमरीकी डालर था, इसका मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में अन्तरराष्ट्रीय गिरावट रहा। 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक-भिन्न आयात गत वर्ष इसी अवधि में 259.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 3.0 प्रतिशत की गिरावट के साथ 251.4 बिलियन अमरीकी डालर रह गया। परिणामतः व्यापार घाटा 2015-16 (जनवरी-अप्रैल) में घटकर 106.8 बिलियन अमरीकी डालर रह गया जबकि पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि में यह 119.6 बिलियन अमरीकी डालर था।

वर्ष 2015-16 के पहले छह महीनों के लिए उपलब्ध भुगतान शेष पर आधारित व्यापार घाटा अप्रैल-सितंबर 2014 में 74.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-सितंबर, 2015 में 71.6 बिलियन अमरीकी डालर था। 2015-16 के पूर्वार्ध में 57.2 बिलियन अमरीकी डालर के निवल अदृश्य प्राप्ति आधिक्य के चलते (2014-15 के पूर्वार्ध में 56.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में) चालू खाता घाटा अप्रैल-सितंबर, 2014 में 18.4 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अप्रैल-सितंबर, 2015 में 14.4 बिलियन अमरीकी डालर था।

भुगतान शेष के आधार पर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निवल संग्रहण 2014-15 और 2015-16 (अप्रैल-सितंबर) में क्रमशः 61.4 बिलियन अमरीकी डालर और 10.6 बिलियन अमरीकी डालर हुआ था। इन संतुलित विप्रेषणों (निजी अंतरण) से कच्चे तेल की निम्न कीमतों ने चालू खाता घाटा कम करने में सहायता की और न्यून परन्तु महत्वपूर्ण पूंजी प्रवाहों के परिणामस्वरूप पूंजी खाता आधिक्य का विस्तार हुआ है। इसके परिणाम से विदेशी मुद्रा भंडार के स्टॉक में वृद्धि हुई जो सितंबर अंत, 2015 में 350.3 बिलियन अमरीकी डालर पर था। विदेशी मुद्रा भंडार का यह स्टॉक 5 फरवरी, 2016 को 351.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था। चूंकि कुछ वित्तीय प्रवाह ऋण सृजक थे इसलिए विदेशी ऋण का कुल स्टॉक मार्चान्त 2015 में 475.2 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर की तुलना में सितंबर अंत 2015 में 483.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था।

वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर (भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर) 62-67 रुपए प्रति अमरीकी डालर (अप्रैल 2015 में 62.75 रुपए प्रति अमरीकी डालर और जनवरी 2016 में 67.25 रुपए प्रति अमरीकी डालर) के बीच थी। 2015-16 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान रुपए की औसत मासिक विनिमय दर 6.3 प्रतिशत कम हो गई। महीना-दर-महीना आधार पर रुपए का 7.1 प्रतिशत मूल्यहास हुआ जो मार्च 2015 में 62.45 रुपए प्रति अमरीकी डालर से जनवरी 2016 में 67.25 रुपए प्रति अमरीकी डालर पर आ गया।

सितंबर अंत 2015 में, भारत का विदेशी ऋण स्टॉक मार्चान्त 2015 की तुलना में 8.0 बिलियन अमरीकी डालर (1.7 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए 483.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया था। भारत के विदेशी ऋण की परिपक्वता पद्धति दीर्घावधिक उधारों की प्रधानता दर्शाती है। सितंबर-अंत 2015 में दीर्घावधिक विदेशी ऋण भारत के कुल विदेशी ऋण का 82.2 प्रतिशत बैठता था, जबकि शेष हिस्सा (17.8 प्रतिशत) अल्पावधिक विदेशी ऋण था। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रति अल्पावधिक विदेशी ऋण का अनुपात मार्चान्त 2015 में 25.0 प्रतिशत की तुलना में 24.6 प्रतिशत था।

### केन्द्र सरकार के वित्त साधन

वर्ष 2014-15 में राजकोषीय समेकन के प्रति दृढ़ वचनबद्धता के चलते सरकार के अधिक-सक्रिय नीतिगत निर्णयों से इस वर्ष राजकोषीय घाटे का निर्धारित लक्ष्य अर्थात् उसे सघउ के 4.1 प्रतिशत पर बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। 2015-16 में राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे के क्रमशः 5,55,649 करोड़ रुपए (सघउ का 3.9 प्रतिशत) और 3,94,472 करोड़ रुपए (सघउ का 2.8 प्रतिशत) की बजटीय व्यवस्था की गई थी। 2015-16 के बजट अनुमान में 'प्रभावी राजस्व घाटा' पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु प्रयुक्त अनुदानों को घटाने के पश्चात राजस्व खाते में असंतुलन 2,83,921 करोड़ रुपए अर्थात् सघउ का 2.0 प्रतिशत अनुमानित था।

वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में कर-सघउ अनुपात 10.3 प्रतिशत, ऋण-भिन्न प्राप्ति-सघउ अनुपात 8.7 प्रतिशत और कुल व्यय-सघउ अनुपात 12.6 प्रतिशत की परिकल्पना की गई थी। सकल कर राजस्व की परिकल्पित वृद्धि 2014-15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 15.8 प्रतिशत थी। 2015-16 के बजट अनुमान में कुल व्यय 2014-15 के संशोधित अनुमान की तुलना में 5.7 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

अप्रैल-दिसंबर 2015 हेतु महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी केन्द्र

सरकार के वित्त साधनों संबंधी आंकड़ों के अनुसार सकल कर राजस्व पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 21.1 प्रतिशत बढ़ा था और यह बजट अनुमान का 66.5 प्रतिशत था। कर-भिन्न राजस्व ने ब्याज प्राप्तियों और लाभांश व लाभों में वृद्धि के कारण अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान पिछले वर्ष की तदनु रूप अवधि की तुलना में 22.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है। दिसंबर-अंत 2015 में, मुख्यतया विनिवेश प्राप्तियों में गिरावट के कारण ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियों में महत्वपूर्ण गिरावट हुई क्योंकि 69,500 करोड़ रुपए की बजटीय राशि की तुलना में मात्र 12,866 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके थे।

प्रमुख सब्सिडियां, ईंधन मूल्य निर्धारण सुधारों और पेट्रोलियम उत्पादों की वैश्विक कीमतों में तीव्र गिरावट के कारण अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान अप्रैल-दिसंबर 2014 की तदनु रूप अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत कम हुई जो पेट्रोलियम सब्सिडी में 22,545 करोड़ रुपए की कमी के कारण हुआ। विलोमतः खाद्य सब्सिडी में 10,278 करोड़ रुपए और उर्वरक सब्सिडी में 8609 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2015-16 (अप्रैल-दिसंबर) के बजट अनुमान में 87.9 प्रतिशत पर राजकोषीय घाटा 82.3 प्रतिशत के पांच-वर्षीय औसत से अधिक परन्तु पिछले वर्ष 100.2 प्रतिशत के तदनु रूप आंकड़े से नीचे था। अप्रैल-दिसंबर 2015 का राजस्व घाटा बजट अनुमान का 81.7 प्रतिशत अनुमानित था और पांच वर्ष के 84.8 प्रतिशत के चल औसत से काफी कम है। संशोधित अनुमान 2015-16 राजकोषीय और राजस्व घाटे को क्रमशः सघउ का 3.9 प्रतिशत और सघउ का 2.5 प्रतिशत रखते हैं।

### संभावनाएं

वर्ष 2015-16 की पहली तीन तिमाहियों में अर्थव्यवस्था के उत्साहवर्धक निष्पादन के आलोक में आर्थिक वृद्धि में तेजी, निम्न मुद्रास्फीति, नियंत्रणीय चालू खाता घाटा, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार, कर राजस्व में वृद्धि, बढ़ते हुए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों के साथ बैंकिंग, अवसंरचना, विद्युत, कराधान, आदि सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधारों को आगे बढ़ाने के सरकार के प्रयासों से चिह्नित अर्थव्यवस्था की निकट भविष्य की संभावनाएं उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। भारत में विकास की गति के सुदृढ़ होने के अनुमान बहु-पक्षीय संस्थाओं ने भी लगाए हैं। तथापि, जो जोखिम अभी भी बने हुए हैं उनमें वैश्विक स्तर पर विकास दर में कमी आना, चीन की अर्थव्यवस्था में मंदी और पुनः संतुलन; वित्तीय बाजारों में वर्धित अस्थिरता और संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपनी मौद्रिक नीति को क्रमिक रूप से कठोर बनाया जाना शामिल हैं। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अर्थव्यवस्था की विकास दर 2016-17 में लगभग 11 प्रतिशत पर रहने की संभावना है।

बृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण  
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य अप्रैल-दिसम्बर		प्रतिशत परिवर्तन अप्रैल-दिसम्बर	
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
<b>संपदा क्षेत्र</b>					
1.	बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (₹ हजार करोड़)#				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	12488	13567	10.8	8.6
	(ख) वर्ष 2011-2012 के मूल्यों पर	10552	11351	7.2	7.6
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (2004-05=100)	172.7	178.1	2.6	3.1
3.	थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100) @	182.8	177.3	3.3	-3.0
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक: संयुक्त (2012=100) @	118.5	124.2	6.1	4.8
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम3) (₹ हजार करोड़)(दिसंबर के अंत में)	10211	11338	10.7	11.0
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) ₹ करोड़	2136855	1915849	5.3	-10.3
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	351614	295812	3.7	-15.9
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात**				
	(क) ₹ करोड़	1458094	1273323	4.5	-12.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	239929	196604	3.5	-18.1
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)**	-111685	-99208	4.3	-11.2
9.	विदेशी मुद्रा भंडार (जनवरी अंत तक)				
	(क) ₹ बिलियन	20314	23586	11.7	16.1
	(ख) बिलियन अमरीकी डालर	328.7	349.6	12.9	6.4
10.	चालू खाता शेष (मिलियन अमरीकी डालर)	-18434	-14375		
<b>सरकारी वित्त साधन (₹ करोड़)^^</b>					
1.	राजस्व प्राप्तियां	693773	803808	9.4	15.9
2.	कर राजस्व (निवल)	545714	622247	5.4	14.0
3.	कर-भिन्न राजस्व	148059	181561	27.3	22.6
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	542615	510189	2.4	-6.0
5.	ऋणों की वसूली	8282	9138	3.0	10.3
6.	अन्य प्राप्तियां	1952	12866	-64.1	559.1
7.	उधार और अन्य देनदारियां	532381	488185	3.1	-8.3
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	1236388	1313997	6.2	6.3
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	883757	968019	8.8	9.5
10.	राजस्व खाता	813270	895386	11.2	10.1
	जिसमें:				
11.	ब्याज भुगतान	275220	302298	10.8	9.8
12.	पूंजी खाता	70487	72633	-13.4	3.0
13.	आयोजना व्यय	352631	345978	0.4	-1.9
	जिसमें:				
14.	राजस्व खाता	282278	230656	3.0	-18.3
15.	पूंजी खाता	70353	115322	-8.9	63.9
16.	कुल व्यय (9+13)	1236388	1313997	6.2	6.3
17.	राजस्व व्यय (10+14)	1095548	1126042	9.0	2.8
18.	पूंजी व्यय (12+15)	140840	187955	-11.2	33.5
19.	राजस्व घाटा (17-1)	401775	322234	8.2	-19.8
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	532381	488185	3.1	-8.3
21.	प्राथमिक घाटा (20-11)	257161	185887	-4.0	-27.7

\*\* सीमाशुल्क आधार पर। # सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े और वृद्धि पूर्ण वर्ष से संबंधित है (अप्रैल-मार्च) ## अप्रैल - सितंबर @ 2015-16 के आंकड़े अनंतिम हैं।

^^ महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा संसूचित आंकड़े।